

**प्रेस सूचना ब्यूरो**  
**भारत सरकार**  
**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**

24-जुलाई-2018 15:50 IST

**पीएमएफबीवाई की समीक्षा**

देश में 2016 के मौसम से प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई थी। योजना के क्रियान्वयन अनुभव की समीक्षा से इकट्ठा करना एक सतत प्रक्रिया है और सभी हितधारकों के परामर्श से किया जाता है।

यह योजना राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) के लिए वैकल्पिक है और अब तक, इस योजना को 27 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू करने का विकल्प चुना गया है। अप्रैल, 2016 में स्थापना के बाद से एक या एक से अधिक सीज़न में, उनके राज्यों में फसलों के लिए जोखिम की धारणा के आधार पर।

यह योजना गैर-रोके जाने वाले प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल की कटाई के बाद के नुकसान के लिए पूर्व-बुवाई से व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है और बीमा राशि के साथ बीमा राशि के बराबर होने के बाद, किसानों को अधिकतम जोखिम कवरेज और न्यूनतम वर्दी पर निर्धारित प्रीमियम दर देय है उनके द्वारा अर्थात् खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए 5%, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50: 50 के आधार पर एकचुअरी / बिड प्रीमियम के संतुलन के साथ। इसके अलावा, बीमा के इकाई क्षेत्र के तहत प्रमुख फसलों के नुकसान के आकलन के लिए गाँव / ग्राम पंचायत स्तर पर और ओलावृष्टि, भूस्खलन और कटाई और कटाई के बाद के नुकसान की स्थानीय आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत खेत स्तर पर उतारा गया है। का आकलन

नुकसान अधिक यथार्थवादी हैं।

मौसमी अनुशासन को और अधिक कठोर बना दिया गया है, जिससे दावों के अधिक त्वरित निपटान की सुविधा है। योजना प्रशासन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल की स्थापना के साथ ही, किसान न केवल योजना के तहत नामांकन कर सकता है, बल्कि अपने दावे के निपटान की पूरी प्रक्रिया को भी ट्रैक कर सकेगा।

खरीफ 2016 और रबी 2016-17 के दौरान रु। 10505.27 करोड़ और रु। 5991.74 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से रु। का दावा है। 10283.91 करोड़ और रु। इन सत्रों के लिए पहले ही 5052.84 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2017 के दौरान, रुपये के कुल अनुमानित दावों में से। 15895.85 करोड़, रुपये का दावा। किसानों को 9628.61 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने दी

\*\*\*\*\*

ए पी एस / आरसीएस